

फ़ाइल संख्या-15011/36/2022-न्याय/ई 6889

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग से संबंधित अप्रैल, 2023 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियों का मासिक सार।

न्याय विभाग से संबंधित अप्रैल, 2023 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

1. दिनांक 19.4.2023 को न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में श्रीलंका के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
2. 19 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय विधि मंत्री और विधि और न्याय राज्यमंत्री ने 1 अप्रैल, 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक न्याय विभाग द्वारा आयोजित "स्वच्छता पखवाड़े" के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेताओं (स्टाफ सदस्यों और बच्चों) को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने व् यू आर कोड के माध्यम से कानूनी सूचना की डिजिटिंग पर पुस्तिका; दिशा के लीगल एस्केप पर कैंटलॉग और कानूनी जागरूकता के लिए डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने के संबंध में पुस्तिका जारी की।

3. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण- II

(क) **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी):** दिनांक 03.04.2023 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर 22.55 करोड़ से अधिक मामलों और कंप्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 21.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(ख) **वर्चुअल कोर्ट:** 21 वर्चुअल कोर्टों में 2.78 करोड़ से अधिक मामले निपटाए गए हैं और दिनांक 31.03.2023 तक 35 लाख से अधिक मामलों में 384 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया है।

(ग) **ई-कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप:** ई-कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की संख्या दिनांक 31.03.2023 तक कुल 1.74 तक पहुंच गई है।

4. टेली लॉ कार्यक्रम:

(क) 30 अप्रैल 2023 तक, 38,13,139 लाभार्थियों को कानूनी सलाह दी गई जिसमें अप्रैल 2023 माह के दौरान, 2,55,744 लाभार्थी भी शामिल हैं।

(ख) माह के दौरान, ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वी एल ई), अर्ध विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी), राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 101 जिलों में आयोजित 351 व्यक्तियों ने 122 प्रशिक्षण और जागरूकता सत्रों/कैंपों में भाग लिया।

5. न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवा):

(क) माह के दौरान, 191 नए प्रो बोनो वकीलों ने न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया। कुल 10,018 वकील (पुरुष- 8417, महिला 1599, ट्रांसजेंडर-02) न्याय बंधु पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं।

(ख) माह के दौरान, उच्च न्यायालयों में 20 नए वकीलों ने नामांकन किया जिससे उच्च न्यायालयों में अब तक कुल 1,276 प्रो बोनो वकील हो गए हैं।

6. पेन इंडिया कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एल एल एल ए पी) :

(क) न्याय विभाग द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (ए पी एस एल एस ए) के सहयोग से 23 अप्रैल 2023 को जारबम गैमलिन लॉ कॉलेज, जोट इटानगर में मेगा कानूनी

सेवा कैंप का आयोजन किया गया था। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अंजॉ और तिराप जिलों में ईच वन टीच टेन (ई1 टी10) पहल के अंतर्गत आयोजित सामुदायिक स्तर के कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीण वृद्धों को प्रशिक्षित किया।

(ख) 14 अप्रैल, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लिया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अभियुक्त/अपराधी की तलाश के लिए असम पुलिस द्वारा तैयार की गई "असम कॉप" मोबाइल आधारित एप्लीकेशन और वाहन ट्रेसिंग ऐप को भी लांच किया गया।

(ग) सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसायटी (सीईसीओईडीईसीओएन) जयपुर, राजस्थान ने राजस्थान के धौलपुर जिले में 9 पंचायत स्तर की संवेदीकरण बैठकें, 19 धानी बैठकें और व्यापक पैमाने पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।
